यहां फंसा पेंच... प्रशासन कोरोना ड्यूटी दिखाते हुए अनुशंसा करे, तभी मिलेगा योद्धा का सम्मान... लेकिन ऐसा हो नहीं रहा

शिक्षकों को कोरोना योद्धा तो मान लिया लेकिन मौत होने पर नहीं दिए ₹50 लाख

भोपाल/इंदौर • डीबी स्टार

शिक्षा विभाग ने कोरोना ड्यूटी में लगे शिक्षकों को 'योद्धा' तो माना है, लेकिन आज तक किसी भी मृत शिक्षक के आश्रितों को न तो 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी और न इलाज का खर्च। और तो और, डिजिटल मृत्यु प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता के कारण 50 हजार रुपए की तात्कालिक सहायता राशि भी परिजन को नहीं मिल सकी है, जबकि सरकार ने खुद माना है कि कोरोना से सालभर में 441 शिक्षकों की मौत हो गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है कि सरकार ने शिक्षकों को भी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया है। सरकार की नीति के तहत कोरोना व्यवस्था में ड्यटी करने वाले शिक्षकों का इलाज शासन के खर्च पर होगा। मौत होने पर कोरोना योद्धा के लिए निर्धारित राशि (50 लाख रुपए) मृतक के परिजन को मिलेगी।

विभाग के अनुसार सालभर में 675 शिक्षकों की मौत हुई है, जिनमें 441 की मौत कोरोना से और 234 का निधन अन्य बीमारियों या दुर्घटनाओं में हुआ है। इसके बावजूद किसी भी शिक्षक के परिजन को सरकार ने 50 लाख रुपए नहीं दिए। सालभर से शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव, मोहल्ला कक्षा, कोरोना सर्वे, टीकाकरण और टोल नाकों से लेकर श्मशान तक में लगाई जा रही है। शिक्षकों की ड्यूटी के ज्यादातर आदेश सोशल मीडिया या सादे कागज पर चार्ट बनाकर जारी किए। यानी, प्रशासन की तरफ से शिक्षकों को बहुत कम आदेश विधिवत या व्यक्तिगत मिले हैं। इसके अलावा शिक्षकों के बीमार होने पर प्रशासन द्वारा उन्हें अच्छे अस्पतालों में भर्ती करवाना तो दूर, इलाज की राशि भी स्वीकृत नहीं की है। शिक्षकों के परिजनों को कोरोना योद्धा का सम्मान भी तभी मिल सकता है, जब प्रशासन उनकी ड्यूटी कोरोना व्यवस्था में दिखाते हुए अनुशंसा करे। प्रशासन की इस लापरवाही का खामियाजा शिक्षकों और उनके परिजन को भुगतना पड़ रहा है। आश्चर्य तो यह है कि जिन शिक्षकों की विधिवत ड्यूटी कोरोना व्यवस्था में लगाई गई थी, उनकी मौत पर भी प्रदेशभर के जिला अधिकारी खामोश हैं।

441 शिक्षकों की मौत हो चुकी है कोरोना से, यह सरकार ने भी माना

50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि भी नहीं मिल रही परिजनों को मौत पर

Badri Gautam

317 शिक्षक और प्राचार्य संक्रमित हो चुके कोरोना से

एडीपीसी एके विजयवर्गीय के मुताबिक भोपाल जिले में 317 शिक्षक एवं प्राचार्य कोरोना से संक्रमित हुए हैं। पिछले साल अप्रैल से अब तक 11 शिक्षकों की कोरोना से मृत्यु हुई है। शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय प्रवक्ता सुभाष सक्सेना एवं शास. अध्यापक संगठन के संयोजक उपेंद्र कौशल ने कहा कि किसी को कोरोना योद्धा का लाभ नहीं मिल रहा है।

ऑनलाइन प्रक्रिया बनी अनुग्रह राशि में रोड़ा

स्कूल शिक्षा और जनजातीय विभाग इन दिनों यह गिनती करने में व्यस्त हैं कि किस जिले में कितने शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई, लेकिन उनके परिवार को क्या और कैसे राहत दी जाए इस बारे में विभाग के पास योजना नहीं है। समग्र शिक्षक संघ का आरोप है कि कोरोना से दिवंगत शिक्षकों की संख्या भले ही सरकारी आंकड़ों में 441 बताई जा रही है, लेकिन वास्तविकता में आंकड़ा इससे ज्यादा है। प्रदेश में डिजिटल मृत्यु प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता के कारण दिवंगत शिक्षकों के आश्रित परिजनों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान भी अटक गया है। नगर निगम के जोन कार्यालयों में ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रमाण-पत्र बनने में समस्या आ रही है। शिक्षकों की मांग है कि भुगतान प्रक्रिया ऑफलाइन की जाए।

परिजन क्लेम करें, हम सरकार से अनुशंसा करेंगे

शिक्षकों को शासन ने पहले ही कोरोना योद्धा मान लिया है, इसलिए जिला प्रशासन अलग से इसकी घोषणा नहीं करेगा। कोरोना में ड्यूटी करते हुए संक्रमित होने पर जिन शिक्षकों की मृत्यु हुई है, उनके परिजन स्थानीय तहसीलदार या एसडीएम के माध्यम से क्लेम करें। इसके बाद जिला प्रशासन सरकार को इसकी अनुशंसा कर देगा।

अभय बेड़ेकर, अपर कलेक्टर और कोरोना ड्यूटी प्रभारी

सीधी बात प्रमोद कुमार सिंह, उप सचिव, स्कूल शिक्षा

कलेक्टर की जिम्मेदारी है कोरोना में लगे शिक्षकों को राशि दिलाना

• प्रदेश में शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना व्यवस्था में लगाई जा रही है। अब तक कितने शिक्षकों का कोरोना से निधन हो चुका है?

- शिक्षकों की कोरोना ड्यूटी जिला प्रशासन लगा रहा है। कोरोना से 441 शिक्षकों का निधन हुआ है।

• महामारी में ड्यूटी करने के बाद भी शिक्षकों को कोरोना योद्धा क्यों नहीं माना जा रहा?

- ऐसे शिक्षकों को भी सरकार ने कोरोना योद्धा का दर्जा दे रखा है।

• लेकिन किसी भी मृत शिक्षक के परिजन को को ₹50 लाख की सम्मान निधि नहीं मिली है?

- यह काम जिला कलेक्टर का है। वे ही इनकी ड्यूटी लगाते हैं। कलेक्टर अनुशंसा करेंगे तो शासन जरूर शिक्षक के परिजनों को राशि देगा। इसी तरह इलाज का प्रबंध भी प्रशासन को ही करना है।

मप्र बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की प्रायोगिक परीक्षाएं स्थगित

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण मप्र बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की प्रायोगिक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके पहले मंडल ने दसवीं और बारहवीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 17 अप्रैल से 20 मई तक कराने के निर्देश दिए थे।

आदेश के अनुसार स्थगित प्रायोगिक परीक्षाओं की नई तारीखें अलग से घोषित की जाएंगी। उल्लेखनीय है कि मंडल ने दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि सीबीएसई बोर्ड ने दसवीं की परीक्षा को निरस्त कर जनरल प्रमोशन देने का निर्णय लिया है। इस साल दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में प्रदेशभर से करीब 19 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।

माशिमं ने जारी किए आदेश

Badri Gautam

दसवीं की नहीं होगी परीक्षा

वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि दसवीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी। किस आधार पर मूल्यांकन होगा, इस संबंध में मंडल के अधिकारियों को अन्य राज्यों के मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेने के लिए कहा है। इसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी।

प्रदेश : 10वीं व 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं स्थगित

भोपाल| प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण मप्र बोर्ड की 10वीं व 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। माशिमं ने कहा है कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए और 15 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन होने के कारण 10वीं व 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित की जाती हैं। माशिमं अब तक 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले पाया है। इससे पहले स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के निर्देश पर 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 माह के लिए स्थगित कर दी थी।

Badri Gautam

सरकार ने स्कूल छोड़ने संबंधी योजना का बजट 90% से भी ज्यादा कम किया

गांवों में बच्चे 10वीं से पहले छोड़ रहे स्कूल

भोपाल • डीबी स्टार

प्रदेश के शहरी इलाकों में भले ही स्कूलों की चकाचौंध बनी हुई हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात इसके उलट हैं। अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के 42% बच्चे 10वीं में पहुंचने से पहले ही स्कूल से तौबा कर लेते हैं। सरकारी आंकड़ों में ही यह सच्चाई सामने आई है। बावजूद इसके सरकार ने इन बच्चों के स्कूल छोड़ने संबंधी योजना का बजट 90% से भी ज्यादा कम कर दिया।

प्रदेश के 20 जिलों के 89 विकासखंडों में आदिवासी विकास विभाग द्वारा स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, इनमें कक्षा पहली से 5वीं के 31% से ज्यादा बालक और 27% से ज्यादा लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। मिडिल स्कूल में यह आंकड़ा करीब 2 गुना हो जाता है।

लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा

Bagri Gautam

समझें छात्रवृत्ति का लेखा-जोखा

केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार ने भी प्रदेश में 9वीं से 12वीं समेत कॉलेजों स्टूडेंट्स के लिए छात्रवृत्ति का सालाना बजट आधा कर दिया है। 2019-20 में 11वीं-12वीं एवं कॉलेज छात्रवृत्ति योजना में 30,700 लाख रुपए का प्रावधान था। जिसे 2020-21 में घटाकर 17,250 लाख रुपए कर दिया गया। महाविद्यालयीन छात्रावासों के लिए 2019-20 में 100 लाख रुपए का प्रावधान था। इसे वर्ष 2020-21 में थोड़ा सा बढ़ाकर 105.20 लाख रुपए किया गया।

एक्सपर्ट व्यू

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित स्कूलों की जरूरत के अनुसार पाठ्य-सामग्री का न होना, प्रशासन की दुविधा के कारण उत्तरदायित्व हीनता का होना और बच्चों के लिए जरूरी गतिविधियों का समय पर न हो पाना इसकी खास वजह है।

डॉ. दामोदर, पूर्व सदस्य, एनसीईआरटी

पिछले 15 साल में स्कूलों की बिल्डिंग की संख्या बढ़ती गई, लेकिन शैक्षणिक गुणवत्ता पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। आदिवासी विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच तालमेल का अभाव होने से भी इस पर बहुत असर हुआ है।

रमाकांत पांडे, शैक्षणिक मामलों के जानकार

बचपन की पीड़ा; जो किताबें नहीं मिल रहीं, उनसे ही ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं शिक्षक

... जबकि नौवीं से 12वीं तक के लिए एनसीईआरटी की वेबसाइट पर नि:शुल्क उपलब्ध है किताबों की पीडीएफ

इंदौर | DBStar

इस समय स्कूल से कॉलेज तब सब बंद हैं। सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई तक पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद कई स्कूल अभिभावकों और विद्यार्थियों की रजामंदी लेकर ऑनलाइन कक्षाएं लगा रहे हैं। रोज किस्तों में तीन-चार घंटे पढ़ाई करवाई जा रही है। लेकिन इस पढ़ाई ने शहर के हजारों बच्चों और उनके माता-पिता के सामने अलग तरह का संकट खड़ा कर दिया है। नौवीं से 12वीं तक के लिए एनसीईआरटी की वेबसाइट पर किताबों की पीडीएफ निःशुल्क उपलब्ध है, लेकिन शिक्षक निजी प्रकाशकों की उन किताबों से पढ़ा रहे हैं, जिनकी पीडीएफ उपलब्ध ही नहीं है। वहीं, पहली से आठवीं तक की किताबें भी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। शिक्षक बच्चों और अभिभावकों पर किसी तरह किताबों की जुगाड़ करने का दबाव बना रहे हैं, जबकि अभी बाजार बंद है।

1. होमवर्क नहीं हो पा रहा, रोज सुनना पड़ती है डांट

महादेव तोतला नगर निवासी कार्तिक पाण्डेय पांचवीं का छात्र है। उसके स्कूल में निजी प्रकाशक की किताबों से ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। शिक्षक 15 दिन से कह रहे हैं कि किताबों की व्यवस्था कर लो। होमवर्क तो दिया जा रहा है, पर बाजार बंद होने से किताबें नहीं मिल रही हैं। किताबें नहीं होने से कार्तिक को रोज डांट पड़ रही है।

2. शिक्षक बोले- किताबों की व्यवस्था करना है

सुदामा नगर का आयुष तिवारी 12वीं का छात्र है। निजी स्कूल के शिक्षक उन्हें रसायन और भौतिकी की पढ़ाई ऑनलाइन करवा रहे हैं। शिक्षकों ने एक पब्लिकेशन की किताबों की व्यवस्था करने के लिए कहा है। आयुष का कहना है बाजार बंद है। शिक्षक दबाव बना रहे कि पढ़ाई करना है तो किताबों की व्यवस्था तो करना ही पड़ेगी।

3. एक ही पब्लिकेशन की किताबों से पढ़ा रहे हैं

गीता नगर निवासी अधर्व कुमार भी सातवीं कक्षा की किताबों के लिए परेशान हो रहे हैं। अधर्व का कहना है कि उनके स्कूल में कोर्स की सभी किताबें एक पब्लिकेशन की चलती हैं। उनके शिक्षक इसी पब्लिकेशन की किताबों से ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन दुकानों बंद होने से किताबें नहीं मिल रही हैं।

4. निजी प्रकाशकों की किताबों से होमवर्क

उषा नगर एक्सटेंशन में रहने वाली प्रगति राजपूत निजी स्कूल में 10वीं की पढ़ाई ऑनलाइन कर रही हैं। वहां के शिक्षक दो प्रकाशन समूहों की किताबों से पढ़ाई करवा रहे हैं। होमवर्क भी इन्हीं किताबों से दे रहे हैं। प्रगति का कहना है कि निजी प्रकाशकों की किताबों की पीडीएफ ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होती हैं।

एक्सपर्ट व्यू

इन दिनों के हालात में निजी प्रकाशकों की किताबों से पढ़ाना उचित नहीं है

एनसीईआरटी के एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अवनीश पाण्डेय बताते हैं नौवीं से 12वीं तक की तमाम किताबें पीडीएफ फॉर्मेट में एनसीईआरटी की वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। इन्हें डाउनलोड कर पढ़ाई की जा सकती है। स्कूल संचालक सामान्य दिनों में एनसीईआरटी के बजाय निजी प्रकाशकों की किताबें चलाते हैं। यह प्रकाशक तमाम शिक्षकों को हर कक्षा और प्रत्येक विषय की किताबों की एक-एक कॉपी नमूने के तौर पर निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इसलिए शिक्षक भी इन्हीं किताबों से पढ़ाई करवाते हैं। इन दिनों जैसे हालात हैं, उनमें निजी प्रकाशकों की किताबों से पढ़ाना उचित नहीं है।

आसान होती है निजी प्रकाशन की किताबों की भाषा

एनसीईआरटी की वेबसाइट पर तमाम कक्षाओं और सभी विषयों की किताबें पीडीएफ फॉर्मेट में निःशुल्क उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी भाषा कठिन होती है। निजी प्रकाशकों की किताबों की भाषा समझ में आने वाली होती है। इससे शिक्षकों को पढ़ाने में आसानी होती है। बच्चे भी इन किताबों से पढ़ाए गई चीजें जल्दी समझ लेते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षक जिन किताबों से पढ़ाएं और जो भी पढ़ाएं, उसका फोटो खींचकर छात्रों को भेज दें ताकि वे किताबें नहीं मिलने की परेशानी से बच सकें। हालांकि किताबें सामने रखकर जो पढ़ाई होती है, उससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। **यूके झा,** अध्यक्ष सहोदय ग्रुप

Badri Gautam

एजुकेशन पोर्टल पर मिलेगी शिक्षकों व स्टाफ की डिटेल

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

मो.नं. 9893231237

Badri Gautam

स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत सभी शिक्षकों व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की पूरी जानकारी एजूकेशन पोर्टल पर पे-रोल एवं ई-सर्विस बुक प्रणाली से ऑनलाइन दर्ज की गई है। प्रत्येक लोक सेवक अपने आईडी पासवर्ड से इस जानकारी को देखेगा और जरूरत पड़ने पर समय-समय पर संकुल प्राचार्य या अधिकारी अपग्रेड करेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं परियोजना समन्वयकों के साथ आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयक्त व जिला संयोजकों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि पदोन्नति, स्थानांतरण, संविलियन, युक्तियुक्तकरण, पदक्रम सूची निर्धारण, गोपनीय चरित्रावली संधारण, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि सभी कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे। ताकि प्रत्येक शिक्षक व कर्मचारी की जानकारी सुचारु बनी रहे। वहीं सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी, त्यागपत्र या मौत होने पर स्टॉप पेमेंट पर्मानेंट आप्शन से शिक्षकों का नाम सूची से हटाया जाएगा। इसी तरह निलंबन होने पर स्टॉप पेमेंट टेम्परेरी आप्शन से पोर्टल पर जानकारी दर्ज होगी।

आज आखिरी दिन, ऑनलाइन जानकारी नहीं दी तो 56 बीएड कॉलेज होंगे काउंसलिंग से बाहर

उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के 591 कॉलेजों से मांगी थी जानकारी

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

उच्च शिक्षा विभाग ने बीएड कॉलेजों में प्रवेश की तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग ने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त सभी 647 बीएड कॉलेजों से आठ मई तक ऑनलाइन डिटेल मांगी थी, लेकिन 56 कॉलेजों ने अभी तक जानकारी नहीं दी है। ऐसे मे यदि शनिवार तक जानकारी सबमिट नहीं होती है तो यह सभी कॉलेज काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे।

अभी तक आगामी सत्र 2021-22 में प्रवेश कराने के लिए विभाग तक 591 कॉलेज ही पहुंच सके हैं। गौरतलब है कि इस वक्त कोरोना संक्रमण तेजी से प्रदेश बढ़ रहा है। इसलिए विभाग ने अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन

करने का निर्णय लिया है। इसके चलते विभाग ने प्रदेश के सभी बीएड कॉलेजों में प्रवेश कराने संबंधित सभी गतिविधियों को ऑनलाइन कर दिया है। विभाग ने कॉलेजों को सत्र 2021-22 में प्रवेश कराने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाते हुए उनसे आठ मई तक सभी जानकारी पोर्टल के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए थे। इसमें अब तक प्रदेश 591 कॉलेजों ने ही भागीदारी की है। अभी भी 56 कॉलेजों ने प्रवेश देने के लिए कोई जानकारी नहीं दी है।

विवि द्वारा जांच पूरी होने पर ही मिलेगी कोर्स की मान्यता

अभी तक उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजों के समस्त प्रकार के दस्तावेजों को देखने के लिए कमेटी द्वारा कराता था। लेकिन, कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने के मद्देनजर उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया है। इस प्रक्रिया के चलते कालेजों द्वारा पोर्टल पर दी गई जानकारी को विवि पहले संबद्धता देते हुए ओके करेगा। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजों के एनसीटीई से कोर्स की मान्यता और प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति द्वारा फीस निर्धारित कराने के पत्र का परीक्षण करेगा। इसके बाद ही उच्च शिक्षा विभाग ऐसे कॉलेजों को आन लाइन काउंसिलिंग में शामिल होने की पात्रता प्रदान करेगा।

Badri Gautam

40 प्रतिशत शासकीय शिक्षकों को नहीं लगे टीके

भोपाल। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज को लगवाने के लिए लोग अपने नम्बर का इंतजार कर रहे हैं। वहीं राजधानी के 40 प्रतिशत शिक्षकों को अभी पहला डोज ही नहीं लग पाया है। वहीं 53 प्रतिशत शिक्षकों को एक डोज लगा है और केवल 7 प्रतिशत शिक्षक ऐसे हैं, जिन?हें वैक?सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। कोरोना टीकाकरण महाअभियान के जोर-शोर से चल रहे प्रचार और कार्यक्रम के बीच, जबकि शिक्षक खुद ही लोगों को टीकाकरण के लिए जागृत कर रहे हैं। यह आंकड़े जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने बनाई शिक्षक सपोर्ट वेबसाइट में प्रदर्शित हुए हैं।

Badri Gautam

वेबसाइट में सरकारी स्कूलों के 173 शिक्षकों ने अपनी जानकारी अपलोड की है, जबकि जिले में लगभग 5,000 शिक्षक कार्यरत हैं। इसमें से 40 प्रतिशत शिक्षकों ने जानकारी दी है कि उन्हें अब तक वैक?सीन का एक भी डोज नहीं लगा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने भोपाल जिले के कोरोना संक्रमित शिक्षकों की मदद के लिए वेबसाइट का निर्माण किया है। इसमें शिक्षकों के लिए प्लाज्मा, ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड की उपलब्धता की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही डॉक्टरों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है। ताकि आपातकाल में शिक्षकों को इससे मदद मिल सके।

शिक्षकों को भी घोषित करें कोरोना योद्धा

प्रतिनिधि, जबलपुर| जिले के ऐसे सभी शिक्षक जिनकी कोरोना ड्यूटी लगाई गई है। उन्हें कोरोना योद्धा घोषित कर उनका बीमा भी करवाया जाए। ऐसी माँग मप्र अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) के अध्यक्ष योगेश चौधरी ने कलेक्टर से करते हुए उचित कार्रवाई की भी माँग की है। उनका कहना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए कलेक्टर के आदेश से शिक्षा विभाग में पदस्थ सभी शिक्षकों की सेवाएँ ली जा रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा नहीं दिया गया है, जबकि अन्य जिलों में ऐसा काफी पहले ही किया जा चुका है। इस दौरान संघ के अजय सोनकर एवं राजेन्द्र तेकाम मौजूद थे।

नहीं मिला एरियर्स

मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का आरोप है कि अभी तक 7वें वेतनमान एरियर्स की तीसरी किश्त का भुगतान नहीं होने से शिक्षकों को इससे वंचित होना पड़ रहा है। उनके अनुसार विकास खंड शिक्षा अधिकारी शहपुरा एवं पनागर की तानाशाही से आदेशों के बावजूद शिक्षक एरियर्स की राशि से वंचित हैं। इस दौरान संघ के अटल उपाध्याय, नरेन्द्र दुबे एवं मुकेश सिंह मौजूद थे।

सहायता केन्द्रों को सैनिटाइज किया जाए- मप्र जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन ने माँग की है कि नगर पालिक निगम के 16 जोनों में से प्रत्येक में कोविड-19 सहायता केन्द्रों की स्थापना की गई है, जिसमें शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के अलावा अन्य भवनों को भी कोविड सहायता केन्द्रों में तब्दील किया गया है। उनके अनुसार इन सभी कोविड सेंटर्स को समय-समय पर सेनिटाइज भी करते रहना चाहिए। इस दौरान समिति के मीनूकांत शर्मा, शकील अंसारी मौजूद थे।

किल कोरोना सर्वे के कर्मचारी परेशान- न्यू बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की प्रांतीय उपाध्यक्ष दुर्गा मेहरा का आरोप है कि शासन द्वारा मैदानी कर्मियों को किल कोरोना सर्वे कार्य में लगाया जा रहा है, लेकिन इन कर्मचारियों को ग्लव्ज, मास्क, पल्स ऑक्सीमीटर एवं दवाएँ तक नहीं दी जा रहीं हैं और इन सारी जीवन रक्षक सामग्रियों के बिना ही उन्हें इस कार्य में लगाया जा रहा है, जिससे वे परेशान हैं। संघ की वीना द्विवेदी एवं जयंती मार्को मौजूद थीं। पी-2

Badri Gautam

कर्मचारियों को वेतन मिलने में हो रही देरी

भोपाल। जिला शिक्षा केंद्र अंतर्गत पदस्थ एपीसी, बीआरसी, बीएसी, जन शिक्षक, संविदा कर्मी एवं अन्य कर्मचारियों को समय पर माह में वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में शासकीय अध्यापक संगठन ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीईओ जिला पचांयत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। शा. अध्यापक संगठन के प्रदेश संयोजक उपेन्द्र कौशल का कहना है कि सीईओ भोपाल द्वारा हर माह वेतन भुगतान की फाइल में अनावश्यक रूप से विलंब करते है, जिसके कारण कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारियों को अनेकों आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड रहा है।

Badri Gautam

संक्रमण कम होते ही निष्कासित अतिथि विद्वानों की होगी बहाली

उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि कोरोना के कारण हो रहा है प्रक्रिया में विलंब

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

प्रदेश में निष्कासित अतिथि विद्वानों की सेवा बहाली के प्रति उच्च शिक्षा विभाग चिंतित दिख रहा है। विभाग का कहना है कि कोरोना का संक्रमण जैसे ही कम होगा तत्काल निष्कासित अतिथि विद्वानों को सेवा में लिया जाएगा। इधर अतिथि विद्वानों का कहना है कि वह विगत 14 माह से बेरोजगारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कोरोना काल के संकट में उनके परिवार का भरण पोषण करना उनके लिए विषम परिस्थिति बनी हुई है। अतिथि विद्वान के नेता डॉ बीएल दोहरे का कहना है कि सेवा से निष्कासित फालेन आउट अतिथि विद्वानों को जल्दी व्यवस्था मे लिया जाये। अतिथि विद्वान परिवार यही उम्मीद रखता है। कांग्रेस सरकार द्वारा 3148 सहायक प्राध्यापक ग्रंथपाल क्रीड़ा अधिकारी की पूर्व सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में नियुक्ति देने से हमारे लगभग 2700 अतिथि विद्वान सेवा से बाहर हुए थे। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय.समय पर सेवा से निष्कासित किए गए अतिथि विद्वानों को व्यवस्था में वापस लेने के लिए पोर्टल चालू किया गया न्यू च्वॉइस फिलिंग के माध्यम से हमारे कई साथी व्यवस्था में वापस आ गए हैं। अभी भी हमारे लगभग 500-600 के आसपास अतिथि विद्वान और नौकरी से बाहर हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी माह में 450 नए पदों की स्वीकृति के लिए फाइल वित्त विभाग में भेजी गई थी।

वित्त मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री दोनों का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भी फाइल अभी भी पृष्ठांकन के लिए वित्त विभाग में वित्त प्रमुख सचिव के पास रखी हुई है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल मौजूदा मुख्यमंत्री स्वयं हमारे आंदोलन में आए हुए थे। उस समय आपके द्वारा ही यह बोला गया था कि टाइगर अभी जिंदा है। मेरी उच्च शिक्षित बहनों को मुंडन कराने एवं दुपट्टा जलाने की नौबत आ गई है। यह मुझसे देखा नहीं गया। अतिथि विद्वानों को रिक्त पदों पर नियमित करना ही पड़ेगा। यदि सरकार नहीं करती है तो वह ईट से ईट बजा देंगे। हालांकि इस समय अतिथि विद्वान गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि उन्हें इस समय लगभग घर बैठे 14 महीने से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना जैसी महामारी में वह अपने घर परिवार का भरण पोषण जैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि निष्कासित अतिथियों को सेवा में लेने के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है। इस कारण वित्त विभाग को भी प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन अभी सरकार के समक्ष महामारी संक्रमण को दूर करने की चुनौती है। जैसे ही यह संकट कम होगा तो अतिथियों की तत्काल सेवा बहाली होगी।

Balki Gautam

गरीब व्यक्तियों को समय पर खाद्यान्न वितरित करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

भोपाल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने सभी एसडीएम और जिला खाद्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि भोपाल जिले में कोविड-19 की रोकथाम के बचाव और गरीबों को तीन माह का एकमुश्त राशन वितरण किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला खाद्य अधिकारी गरीबों को समय पर खाद्यान्न वितरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने खाद्यान्न वितरण प्रणाली में सभी अधिकारी पारदर्शिता लाएं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिले के सभी गरीबों को अप्रैल, मई व जून का राशन नि:शुल्क देने का निर्णय लिया है। माह अप्रैल का राशन वितरण हो चुका है। मई एवं जून का राशन दिया जाना है। कलेक्टर ने सर्वप्रथम जिला खाद्य अधिकारी से दुकानों के खुलने के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि कुछ दुकानें खुल चुकी है, कुछ खुलना शेष हैं। जिस पर कलेक्टर द्वारा गहन असंतोष प्रकट करते हुए खाद्य अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारियों, एसडीएम व सीईओ जनपद को निर्देश दिए हैं कि फील्ड में जाकर सभी उचित मूल्य दुकानें खुलवाएं और खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि इस कार्य को प्राथमिकता दें। और यह सुनिश्चित करें कि 15 मई के पूर्व सभी को खाद्यान्न मिल जाये।

सर्व शिक्षा कर्मचारियों को नहीं हुआ अप्रैल का वेतन भुगतान

जिला पंचायत ने कहा वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, बीआरसीसी ने समय पर नहीं भेजी संक्रमित शिक्षकों की जानकारी

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

सर्व शिक्षा अभियान के अधीन डीपीसीसी लेकर बीआरसी कार्यालयों और संकुल केंद्रों पर काम कर रहे शैक्षणिक एवं अन्य स्टाफ को अप्रैल माह के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इधर जिला पंचायत में अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। कर्मचारियों का कहना है कि राजधानी भोपाल के जिला शिक्षा केंद्र अंतर्गत पदस्थ एपीसी, बीआरसी, बीएसी जन शिक्षक संविदा कर्मी एवं अन्य कर्मचारियों को मय पर माह में वेतन भुगतान नही हो पा रहा है। ज्ञात हो कि उक्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान की फाइल पहले जिला पंचायत से अनुमोदन होने के पश्चात ही वेतन भुगतान की कार्यवाही होती है। अन्य फाइलों अथवा अन्य कार्यों को लेकर हर माह वेतन भुगतान की फाइल में अनावश्यक रूप से विलंब किया जा रहा है। जिसके कारण डीपीसी कार्यालय अंतर्गत पदस्थ उपरोक्त कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। समय पर वेतन नहीं मिल पाने से इन कर्मचारियों को अनेकों आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसी के बैक किश्त होम लोन किश्त परिवारिक समस्या बच्चों के फीस बीमारी का इलाज इत्यादि समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के दौरान जहा कर्मचारी पहले से ही आर्थिक रूप से पीड़ित है। वही समय पर वेतन ना मिल पाने से वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाहन कैसे करें। जन शिक्षक एवं अध्यापक नेता उपेंद्र कौशल का कहना है कि ऐसे समय पर हर माह कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर इनकी आर्थिक समस्याओं का निराकरण कर उदारता दिखाई जाए। वेतन भुगतान की फाइल लटकाकर कर्मचारियों को आर्थिक रूप से परेशान होना पड रहा है। जबकि शासन के स्पष्ट आदेश है कि हर कर्मचारी को माह की पहली तारिख को वेतन भुगतान किया जाना सुनिश्चित हो।

वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है: विकास मिश्रा

इस संबध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकास मिश्रा का कहना है कि सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत लोक सेवकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा है कि कुछ जन शिक्षकों एवं कर्मचारियों को कोरोना हो गया था। उन्होंने कहा है कि इसके कारण वेतन भुगतान में थोड़ा विलंब हुआ है। उन्होंने उन्होंने कहा है कि जल्द ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। इधर जानकारी यह भी है कि कुछ जन शिक्षकों एवं कर्मचारियों को कोरोना हो गया था जो घरों में ही क्वारेंटाइन थे। इसकी प्रमाणित जानकारी समय से बीआरसीसी द्वारा डीपीसी कार्यालय को भेजी जानी थी। बीआरसीसी द्वारा समय पर यह जानकारी नहीं भेजने के कारण वेतन में विलंब हुआ है। इसके पीछे बीआरसीसी की लापरवाही भी मानी जा रही है। जबकि शासन के आदेश अनुसार डीपीसी और बीआरसीसी कार्यालय में 10 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य थी। उसके बाद भी इस कार्य में लापरवाही हुई है। जिसके कारण निर्दोष जन शिक्षकों बीएससी एपीसी एवं अन्य कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है।

स्थाई कर्मचारियों को पिछले दो महीने से नहीं दिया गया है वेतन

भोपाल। वन एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन स्थाई एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन का भुगतान नही हुआ है। आरोप है कि नौकरशाही के कारण वेतन मे विलंब हुआ है। जिसके कारण परिवारों मे आर्थिक तंगी का माहौल बन गया है। स्थाई कर्मी कल्याण संघ के प्रांत अध्यक्ष शारदा सिह परिहार ने बताया कि मध्य प्रदेश के स्थाई कर्मियों को माह मार्च अप्रैल 2021 का वन मंडल सिवनी एवं उत्तर वन मंडल शहडोल का वेतन भुगतान आज दिनाक तक नही किया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग सिवनी मे भी विगत 3 माह से वेतन भुगतान नही किया गया। इस भीषण महामारी के दौर पर वेतन भुगतान न होना विकट समस्याओं को जन्म देता है। स्थाई कर्मी अपनी राशन सामग्री स्कूल फीस बिजली बिल जमा करने में असमर्थ है।

कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि नौकरशाही कर रही लापरवाही

मानसिक तथा आर्थिक रूप से प्रताड़ना का सामना कर रहा है। शीघ्र वेतन भुगतान कराए जाने के संबंध मे विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से पत्राचार कर माग की जा रही है। आरोप है कि नौकरशाह बेपरवाह बने हुए है। जिससे स्थाई कर्मियों का परिवार भूखों मरने की कगार पर आता जा रहा है। संगठन के महामंत्री गोविंद तिवारी ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में रोजमर्रा की चीजें दुकानों से उधार प्राप्त कर ली जाती थी। लेकिन इस महामारी के दौर में लॉकडाउन के चलते यह व्यवस्था भी सुलभ नहीं है। ऐसी स्थिति में आखिर रोजमर्रा की चीजें कैसे प्राप्त की जाए यह एक बड़ी समस्या स्थाई कर्मी के समक्ष आ गई है। अगर शीघ्र वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो फिर आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

Badri Gautam

दमोह, गुना व रतलाम के कलेक्टर बदले, दमोह एसपी को भी हटाया

भोपाल, (प्रसं)। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं-

भाप्रसे के पांच अधिकारियों की पदस्थापना

Badri Gautam

नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
गोपाल चंद्र डाड	कलेक्टर रतलाम	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
कुमार पुरूषोत्तम	कलेक्टर गुना	कलेक्टर रतलाम
तरूण राठी	कलेक्टर दमोह	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
अनूप कुमार सिंह	अपर कलेक्टर जबलपुर	यथावत
फ्रेंम नोबल ए	अपर कलेक्टर बालाघाट	कलेक्टर गुना
एस. कृष्ण चैतन्य	अपर आयुक्त नपानि, इंदौर	कलेक्टर दमोह

- दमोह एसपी हेमंत चौहान को हटाकर एआईजी पीएचक्यू भोपाल पदस्थ किया है, जबकि डीआर तेनीवार सेनानी 24वीं वाहिनी विसबल जावरा रतलाम को दमोह एसपी बनाया है।

एक जून से केवल यूडीआईडी पोर्टल से ही मिलेंगे दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

भोपाल, (प्रसं)। सामाजिक न्याय एवं नि :शक्तजन कल्याण मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया है कि प्रदेश में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एक जून 2021 से यूडीआईडी पोर्टल http:// www. swavlambancard. gov.in पर राज्य शासन द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र शासन द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि आगामी एक जून 2021 से नवीन एवं नवीनीकरण सहित सभी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र केवल यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार जारी किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

Badri Gautam

कोरोना काल में भूल सुधरे और स्वास्थ्य की सरकारी सेवाएं गरीबोन्मुखी बनें : उमा

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा नीतियों पर सवाल उठाते हुए इनमें सुधार की आवश्यकता वताई है। कई ट्वीट में उन्होंने कहा कि पेट भरने लायक कमाई करने वालों के पास भी निजी स्कूल की महंगी फीस देने के अलावा कोई विकल्प नहीं वचा तो अभावग्रस्त लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हो गए और उन्हें अपने प्रियजनों की जान वचाने के लिए जेवर, जमीन तथा घर वेचकर निजी अस्पतालों के विल देने पड़े। शायद इस कोरोना संकट में हम अपनी भूल सुधारने के लिए विवश हो जाएं और स्वास्थ्य की सरकारी सेवाओं को गरीवोन्मुखी कर सकें।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार में मंत्री रहने के दौरान मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि जो भी मुनाफा आए, उसे शिक्षा और स्वास्थ्य की सरकारी सेवाओं पर खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे देश की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सरकारी व्यवस्थाएं वहुत ही खराव हैं। इसी कारण कोरोना संकट गहरा गया। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को ढांचा गिर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसे फिर से खड़ा कर सकते हैं। दोनों सेक्टर में निजीकरण के वाद से ही गरीवों के लिए संकट शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि आर्य समाज एवं सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा के क्षेत्र में तो कई चिकित्सकों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाभाव से काम किया। हालांकि वाद में व्यवसायिकता के चलते अन्य जगह अमानवीयता के साथ फीस वसूली जाने लगी।

उमा भारती

Badri Gautam

वर्क फ्रॉम होम सुविधा ले सकेंगी

दिव्यांगों व गर्भवती महिला कर्मियों को ऑफिस आने की जरूरत नहीं

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑफिस अटेंडेस नियमों में कई बदलाव किए हैं। कई तरह के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दी गई है।

केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को जारी एक संशोधित सर्कुलर में कहा गया है कि दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को ऑफिस आने की जरूरत नहीं होगी और वे वर्क फ्रॉम होम सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। गौरतलब है कि देश में कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है।

Badri Gautam

अटेंडेंस रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सचिवों की

संशोधित नियमों में कहा गया है कि दफ्तरों और अन्य जगहों पर कोविड पॉजिटिव मामलों को देखते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने कर्मचारियों के अटेन्डेंस को रेगुलेट करें।

कंटेनमेंट जोन के कर्मी फोन से संपर्क में रहें

ऑर्डर में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के अधिकारियों, कर्मचारियों को तब तक वर्क फ्रॉम होम की इजाजत है जब तक उनका यह जोन डीनोटिफाइड नहीं हो जाता यानी सामान्य घोषित नहीं हो जाता। 'कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारी और कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं और उन्हें हर समय फोन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संपर्क में रहना होगा।

स्कूल खुलेंगे या नहीं इस पर 15 मई के बाद होगा फैसला, पेरेंट्स बोले- न वैक्सीन, न व्यवस्थाएं... आखिर कैसे रहेंगे बच्चे सुरक्षित ?

अब कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना ने बढ़ाई चिंता, अभी स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं अभिभावक

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर स्कूली व्यवस्था को बेपटरी कर दिया है। परीक्षाओं के साथ-साथ इस बार ऑनलाइन कक्षाएं भी संक्रमण से प्रभावित हुई हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग ने दसवीं-बारहवीं की कक्षाओं को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए एक माह तक ऑनलाइन कक्षाएं बंद रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में फिलहाल बच्चे घरों में हैं और स्कूलों के खुलने को लेकर असमंजस बरकरार है। इसके साथ ही अब कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। अभिभावकों का कहना है कि फिलहाल 6 माह तक स्थिति सुधरती नजर नहीं आ रही है।

ऐसे में फिलहाल स्कूलों को खोलने कोई गुंजाइश नहीं है। मुख्य बात यह भी है कि स्कूली बच्चों के लिए न तो कोई वैक्सीन उपलब्ध है और न स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था, ऐसे में बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्कूलों के खुलने को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि फिलहाल 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू है। इसके बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोलने के संबंध में कोई निर्णय लिए जाएगा।

कोई गुंजाइश नहीं

कोरोना संक्रमण जिस हिसाब से तेजी से फैल रहा है और सरकार जिस धीमी गति से वैक्सीनेशन कर रही है। ऐसे में फिलहाल 6 माह तक तो स्थिति सुधरती नजर नहीं आ रही है। कई जगह से यह भी सुनने में आ रहा है कि कोविड-19 की तीसरी लहर भी आएगी। ऐसे में फिलहाल स्कूलों को खोलने कोई गुंजाइश नहीं है। एक मुख्य बात यह है कि स्कूली बच्चों के लिए न तो कोई वैक्सीन उपलब्ध है और न स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था हो पाएगी।

प्रबोध पंड्या, महासचिव, पालक महासंघ, मप्र

अभी सही समय नहीं

यह समय मेडिकल इमरजेंसी का है। स्कूलों को खोलना फिलहाल बिल्कुल सही नहीं होगा। शिक्षा व्यवसाय नहीं है, यह एक समाज सेवा कार्य है। स्कूलों को अब इस बात को समझना चाहिए कि इस दौर में वह भी लोगों की मदद के लिए आगे आए और एंबुलेंस, चिकित्सा जैसी सेवाएं भी बच्चों को उपलब्ध कराएं। क्योंकि भविष्य में कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना भी है।

अखिलेश शर्मा, पेरेंट्स

कोई समझौता नहीं होगा

वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्कूल खोलना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि अभिभावक के लिए सबसे मुख्य बच्चे की सुरक्षा होती है। अगर स्कूल खोले भी गए तो हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। हम बच्चे को एक साल घर बैठा सकते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। वैसे भी बीते डेढ़ साल से हम ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

रिमता शेट्टी, पेरेंट्स

परिस्थिति के अनुसार लिया जाएगा निर्णय

फिलहाल 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू है। इसके बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही परिस्थिति अनुसार स्कूलों को खोलने के संबंध में कोई निर्णय लिए जाएगा।

इंदरसिंह परमार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्कूल शिक्षा

Brijon Gautam

20 जून की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को लेकर भी है असमंजस

एमपी पीएससी जून में नए सिरे से जारी करेगा एग्जाम कैलेंडर, आगे बढ़ेंगी सारी परीक्षाएं

भास्कर संवाददाता | इंदौर

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) का इस वर्ष का यानी 2021 में होने वाली परीक्षाओं का पूरा एग्जाम कैलेंडर नए सिरे से जारी होगा। इसमें कई परीक्षा अगले साल पर शिफ्ट होंगी।

कोरोना संक्रमण की वजह से 11 अप्रैल को स्थगित हुई राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 अब 20 जून को भी संभवतः नहीं हो पाएगी। पीएससी के लिए अब चुनौती बढ़ गई है। दरअसल, पीएससी ने भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से लेकर इंटरव्यू और रिजल्ट तक की तारीखें भी घोषित कर दी थीं। इसने 2021 का पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी किया था। इसमें 2019 की मुख्य परीक्षा से लेकर 2020 की राज्य सेवा प्रारंभिक और मुख्य सहित 2021 की भी कई परीक्षाएं शामिल थीं। अब सवाल यह है कि अगर 2020 की प्रारंभिक परीक्षा ही 20 जून को होगी तो 2021 की परीक्षाएं कब और कैसे होंगी? क्योंकि कोरोना संक्रमण से हालात सामान्य होने में अभी कम से कम डेढ़ माह का और समय लग सकता है। पीएससी का कहना है कि परिस्थितियों के मुताबिक हालात देखकर नया एक्जाम शेड्यूल जारी करेंगे।

बीएड की एफिलिएशन और प्रवेश प्रक्रिया रुकी, अब जून में संभव

इंदौर | कोरोना के बढ़ते प्रकोप और यूजी की फाइनल एग्जाम नहीं होने की वजह से इसी माह होने वाली बीएड कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया रोक दी गई। साथ ही बीएड कॉलेजों की एफिलिएशन और मान्यता की एनओसी से जुड़ी प्रक्रिया भी रोक दी गई। यह प्रक्रिया इसी सप्ताह प्रारंभ होना थी, जबकि 25 मई के बाद एडमिशन प्रक्रिया शुरू होना थी। उच्च शिक्षा विभाग का कहना है अब जून में ही एफिलिएशन और जून अंत तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने पर विचार करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसका पूरा शेडयूल जारी किया था, जो निरस्त हो गया।

Badri Gautam

विद्यार्थियों ने पेंटिंग बनाकर दिया कोरोना से पार पाने का संदेश

रंग● ऑनलाइन पेंटिंग स्पर्धा में मानवीय संवेदनाएं अभिव्यक्त

भोपाल(नवदुनिया रिपोर्टर)। नेहरू युवा केंद्र भोपाल, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कला के माध्यम से कलाकारों को प्रोत्साहन और समाज में सकारात्मक संदेश देने की पहल के तहत ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें प्रदेश भर के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी पेंटिंग से वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया। जिला युवा अधिकारी डॉ. सुरेंद्र शुक्ला ने बताया कि प्रतिभागियों ने स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत, जीत जाएंगे हम, हमारे कोरोना वॉरियर्स, जन जागरण से टीकाकरण जैसे विषयों पर पेंटिंग बनाते हुए सकारात्मक संदेश दिया।

डॉक्टर व पुलिस के प्रति आभार व्यक्त करती पेंटिंग। ● सौजन्य

कोरोना योद्धाओं को नमन: भोपाल के प्रतिभागी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने पोस्टर के माध्यम से वैक्सीन की सार्थकता को चित्रित किया है। वैक्सीन ही वह संजीवनी है जो कोरोना महामारी से बचाव में सहायक है।नसरुल्लागंज की कक्षा 12वीं की छात्रा श्रुति अग्रवाल ने पेंटिंग के माध्यम से 'घर पर रहें सुरक्षित रहें' का संदेश दिया। भूपेंद्र चौहान ने अपनी पेंटिंग से डॉक्टर, नर्स एवं पुलिस जवानों के प्रति आभार व्यक्त किया। साविर ने टीकाकरण की अपील की। पेंटिंग के माध्यम से दिखाया कि हमें बिना किसी संकोच के वैक्सीन लगवाना

पेंटिंग में वैक्सीनेशन का संदेश● नवदुनिया

चाहिए, महामारी के समय में वैक्सीन ही संजीवनी है। हम इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करें।

नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी: सोनाली चौहान ने पेंटिंग से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और टीकाकरण की महत्ता को अभिव्यक्त किया। नियमों का पालन करके हम महामारी से बच सकते हैं। वैक्सीन हमारा सुरक्षा कवच है।

मन के हारे हार है, मन के जीते जीत: मयूरी नेमा ने बताया कि कोरोना की लड़ाई में मनोबल जरूरी है, जिस प्रकार सेना, पुलिस, हमारे चिकित्सक दिन रात जिस हौसले के साथ कोरोना से लड़ रहे हैं, उसी हौसले से हमें भी लड़ना है, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। दिव्यांश नेमा ने पेंटिंग के माध्यम से सभी कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट किया। स्पर्धा में प्राप्त सभी पेंटिंग्स को नेहरू युवा केंद्र के फेसबुक पेज पर प्रदर्शित किया जाएगा।

Badri Gautam

यूनिवर्सिटी एग्जाम आगे बढ़े, चाहें तो ऑनलाइन कराएं

सिटी रिपोर्टर| यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी को मई में होने वाली ऑफलाइन परीक्षाओं को फिलहाल के

आयोजित ना करने का आदेश दिया है। यूजीसी ने कहा, यूनिवर्सिटी मई में ऑफ्लाइन परीक्षाएं न कराएं और स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा के बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का फैसला लें। इससे पहले, शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी को मई की परीक्षा स्थगित करने को कहा था।

डीआरडीओ से अप्रेंटिस के लिए 17 तक करें अप्लाई

सिटी रिपोर्टर| डीआरडीओ ने अप्रेंटिस के 79 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इन पदों

के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इच्छुक प्रतिभागी 17 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 14 साल के ऊपर होनी चाहिए। कैंडिडेट्स NAPS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Badri Gautam

फसाई में भर्ती के लिए आवेदन 15 मई तक

सिटी रिपोर्टर| फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (फसाई) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए

नोटिफिक्केशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। योग्य और इच्छुक कैंडिडेट्स अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 38 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक कैंडिडेट्स अथॉरिटी की वेबसाइट www.fssai.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

पहले राउंड की GATE काउंसिलिंग 28 मई से

रिपोर्टर • IamBhopal
Mobile no. 9827080406

Badri Gautam

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) दिल्ली ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट 2021) की काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। अब यह प्रक्रिया 28 मई, 2021 से शुरू होगी।

देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए काउंसिलिंग पांचवें राउंड में आयोजित की जाएगी। इसके तहत पहला राउंड में 28 मई से शुरू होगी और 30 मई को आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरा राउंड 2 4 जून 2021 से 6 जून को आयोजित किया जाएगा। गेट परीक्षा 27 विषयों के लिए आयोजित की जाती है। इस साल गेट में दो नए विषय पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग व मानविकी और सामाजिक विज्ञान जोड़े गए हैं।

आईआईटी व एनआईटी में मिलता है प्रवेश

इस ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा के जरिए देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों (आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी एवं अन्य) में एमटेक, एमई और पीएचडी जैसे मास्टर व डॉक्टोरल कोर्सेज में दाखिला मिलता है। इसके अलावा देश की बहुत सी पीएसयू कंपनियां भी इसी परीक्षा के जरिए भर्तियां करती हैं।

सीबीएसई स्कूलों में 15 से 20 प्रतिशत तक हुए एडमिशन, लेकिन एमपी बोर्ड के स्कूलों में अभी तक जीरो

शीघ्र कम नहीं हुआ कोरोना तो यह सत्र भी हो जाएगा जीरो

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
मो.नं. 9893231237

कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल-कॉलेज बंद हैं, ऐसे में पिछले सत्र में अधिकांश स्कूलों में एडमिशन शून्य थे, इस बार भी स्कूलों में वही स्थिति है। राजधानी के सीबीएसई स्कूलों में जनवरी से एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने के कारण 15 से 20 प्रतिशत ही एडमिशन हुए हैं, लेकिन एमपी बोर्ड प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में तो एडमिशन शुरू भी नहीं हुए। ऐसे में यदि शीघ्र ही कोरोना नियंत्रित नहीं होता, तो यह सत्र भी जोरी ही जाएगा। आमतौर पर सीबीएसई स्कूलों में जनवरी से नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो जाते हैं। ऐसे में राजधानी के सहोदय ग्रुप के सभी स्कूलों में जनवरी

व फरवरी में 15 से 20 प्रतिशत स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है। उसके बाद कोरोना संक्रमण बढ़ा और स्कूल बंद होने के साथ ही एडमिशन प्रक्रिया रोक दी गई है। इन स्कूलों ने पिछले वर्ष मार्च तक एडमिशन पूरे कर लिए थे। केजी-1 में एडमिशन होने से इन स्कूलों में पिछले सत्र का रोटेशन तो बन गया था। लेकिन इस बार नर्सरी में न के बराबर एडमिशन हुए हैं, तो पूरा सत्र खाली जाएगा और अगले सत्र में केजी-1 में बच्चे नहीं होंगे।

डर के मारे नहीं हो रहे एडमिशन

सीबीएसई स्कूलों ने जनवरी फरवरी में ऑफलाइन प्रवेश शुरू किए थे। फरवरी के बाद स्कूल बंद हो गए। ऐसे में ऑनलाइन पोर्टल से प्रवेश शुरू हुए, लेकिन उसमें किसी पैरेंट ने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसके पीछे अनिश्चतता का माहौल बताया जा रहा है। पहला तो कोरोना को देखते हुए आगे स्कूल लगेंगे या नहीं। यह साफ नहीं है।

स्कूलों की स्थिति और भी खराब

एमपी बोर्ड के में अप्रैल में प्रवेश शुरू होते हैं, लेकिन मार्च से स्कूल बंद हो गए हैं। ऐसे में सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में अभी एडमिशन शून्य हैं। 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन के बाद एमपी बोर्ड के स्कूलों में नर्सरी, केजी-1 या फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं हो पाए और पूरा साल जीरो हो गया था।

क्या कहते हैं स्कूल संचालक

हमने जनवरी से एडमिशन प्रक्रिया शुरू की थी और पिछले वर्ष कोरोना की मार के कारण हमने पैरेंट्स पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया था। इसी का परिणाम है कि प्रवेश प्रक्रिया धीमी चली और बमुश्किल 20 प्रतिशत एडमिशन हो सके हैं, जबकि हर बार लगभग 250 एडमिशन होते हैं, लेकिन अभी तक नर्सरी में सिर्फ 50 बच्चे ही आए हैं।

विनीराज मोदी, संचालक, ज्ञानगंगा इंटरनेशनल एकेडमी, भोपाल

कोरोना के कारण लोगों भविष्य सुरक्षित नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि हमने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू की है, लेकिन पैरेंट्स रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। जनवरी-फरवरी में ऑफलाइन 50 एडमिशन हुए हैं। आमतौर लगभग 300 बच्चे नर्सरी में एडमिशन लेते थे। यदि यही स्थिति रही तो इन्हीं 15 फीसदी बच्चों के साथ सत्र शुरू करना होगा।

बाबू थॉमस, संचालक, सेंट जार्ज स्कूल ग्रुप

एमपी बोर्ड के स्कूलों में अप्रैल से प्रवेश शुरू होता है, लेकिन मार्च से कोरोना के कारण स्कूल बंद हो गए हैं। परिणामस्वरूप अभी तक किसी भी स्कूल में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। पिछले वर्ष भी मार्च से लॉकडाउन लगने के कारण नर्सरी में एडमिशन नहीं हुए थे, पूरा सत्र शून्य रहा है। अब इस बार नर्सरी में तो बच्चे होंगे नहीं और केजी-1 की क्लास भी खाली रहेगी।

अजीत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन, मप्र

Badri Gautam

बीएसएसएस में ई-कंटेंट के जरिए स्टूडेंट्स कर रहे पढ़ाई

दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी ले रहे सबजेक्ट वीडियो का लाभ

रिपोर्टर • IamBhopal
Mobile no. 9582826011

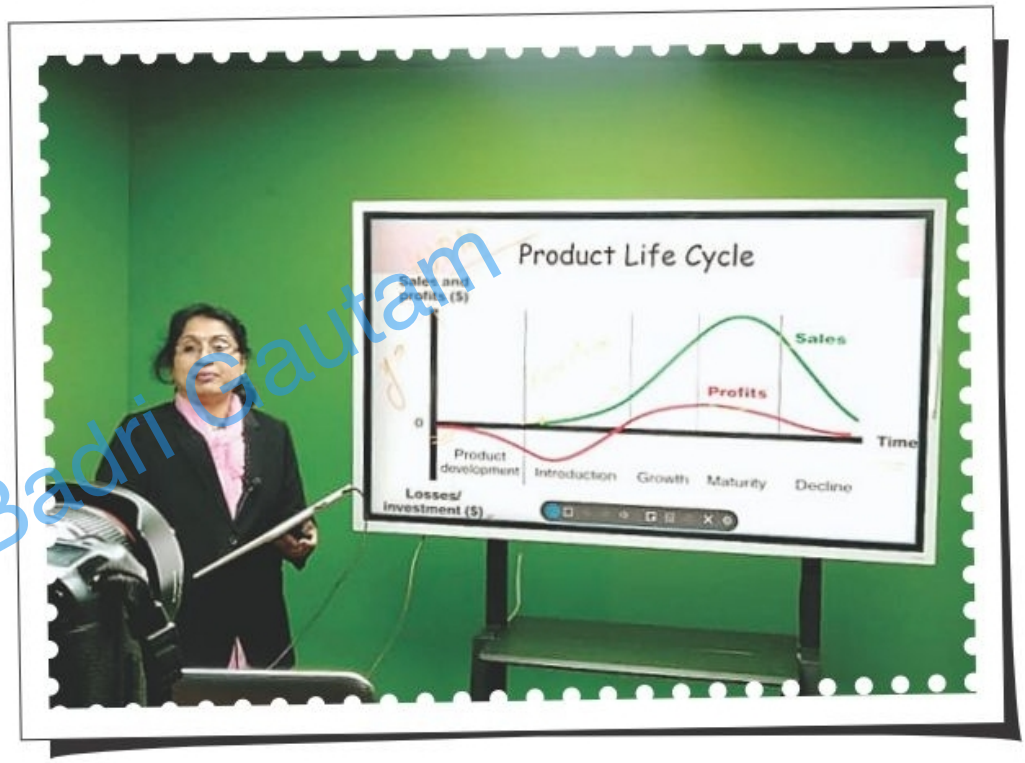

Badri Gautam

कोविड-19 के चलते इस सत्र में महाविद्यालयों में अधिकतर कक्षाओं के न लगने से लगभग पूरा सत्र ऑनलाइन शिक्षा का ही रहा है। ऐसे में स्टूडेंट्स यूट्यूब पर ई-कंटेंट देखकर अपनी पढ़ाई करके संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालातों को देखते हुए द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ने बीते वर्ष लॉकडाउन के दौरान ही प्रत्येक विषय की विषय सामग्री के वीडियो लेक्चर अपने ही स्टूडियो में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए थे।

ऐसे में हर दिन निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार तीन या चार रिकार्डिंग करते हुए कॉमर्स, ह्यूमेनिटीस, विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मैनेजमेंट के पूरे सिलेबस के 350 से अधिक वीडियो तैयार करके कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिसका लाभ घर बैठे बीएसएसएस के स्टूडेंट्स के अलावा दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी लाभ ले रहे हैं।

ई-कंटेंट इंचार्ज तनूजा खान ने बताया कि हमारी तरफ से हमने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा तय पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए ई-कंटेंट तैयार किया है और प्रयास किया है कि गुणवत्ता तथा प्रस्तुतिकरण बेहतर हो।

वीडियो निर्माता योगेश पांडे और वीडियो एडिटर संदीप का कहना है कि हमने साल भर में लगातार रिकॉर्डिंग और एडिटिंग करके ये वीडियो तैयार किए हैं वेबसाइट पर अपलोड करने के पहले हम सबजेक्ट एक्सपर्ट से चेक करवाते हैं, जिससे सही मटेरियल स्टूडेंट्स तक पहुंच सके।

आईआईटी चेन्नई की एचसीईई परीक्षा हुई पोस्टपोन

भोपाल। इंडियन इंस्टीटूट ऑफ टेक्नोलॉजी (चेन्नई) ने ह्यूमेनिटीज एंड सोशल साइंसेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन (एचसीईई) परीक्षा कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दी गई है। यह परीक्षा इससे पहले 13 जून को होने वाली थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब नई तारीख की जानकारी परीक्षा से 15 दिन पहले जारी की जाएगी। कैंडीडेट अधिकारिक वेबसाइट पर नई तारीख देख सकेंगे। 11 मई तक स्टूडेंट्स अपना एप्लीकेशन स्टेट्स देख सकते हैं। यह पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड एम इन डेवलपमेंट एंड ह्यूमेनिटीज प्रोग्राम है जिसकी पढ़ाी आईआईटी चेन्नई कराता है।

Badri Gautam

वेतन मिलने में हो रही देरी, अध्यापक संगठन ने जताई नाराजगी

भोपाल। जिला शिक्षा केंद्र अंतर्गत पदस्थ एपीसी, बीआरसी, बीएसी, जन शिक्षक, संविदा कर्मी एवं अन्य कर्मचारियों को समय पर माह में वेतन भुगतान नही हो पा रहा है। ऐसे में शासकीय अध्यापक संगठन ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीईओ जिला पचांयत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। शासकीय अध्यापक संगठन के प्रदेश संयोजक उपेन्द्र कौशल का कहना है कि उक्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान की फाइल पहले जिला पंचायत से अनुमोदन होने के पश्चात ही वेतन भुगतान की कार्यवाही होती है। सीईओ द्वारा अन्य फाइलों या अन्य कार्यो के लिए हर माह वेतन भुगतान की फाइल में अनावश्यक विलंब होता है। इससे डीपीसी के अंतर्गत पदस्थ कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिससे आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं।

Badri Gautam

संभलिए... पर्यावरण बचाइए, नहीं तो बच्चों के कंधे पर होंगे ऑक्सीजन के उपकरण

चलो बच्चों से सीखें

ऑक्सीजन का महत्व समझाने के लिए 4 वर्ष के दियांश दूधवाला ने अपनाया अनोखा तरीका

सूरत | कोरोना वायरस की मार और ऑक्सीजन संकट के बीच सूरत में चार साल के दियांश दूधवाला ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर पर्यावरण संरक्षण की अपील की। एक पारदर्शी कंटेनर में एक पौधा रख कर इसे नली-मास्क से जोड़कर सड़क पर मार्च कर संदेश दिया कि पौधा ऑक्सीजन का उत्सर्जन कर रहा है। नली-मास्क सहित डिवाइस के जरिए सांस ली जा रही है। जीत फाउंडेशन इंडिया नामक संस्था के सहयोग से दियांश दूधवाला इस उपकरण के साथ हीरानगरी में जगह-जगह चौराहों पर मार्च कर जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय हैं। दियांश दूधवाला कहते हैं- 'पेड़-पौधे-वृक्ष पृथ्वी पर बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये हैं तो ऑक्सीजन है। अब भी यदि लोगों ने वृक्षों का ख्याल रखना शुरू नहीं किया तो वे दिन दूर नहीं, जब बच्चों को कंधे पर स्कूल बैग की बजाय ऑक्सीजन के लिए डिवाइस लेकर चलना पड़ेगा।"

Badri Gautam